CORRUPTION HAMMERING INDIAN ECONOMY

DR VARINDER BHATIA
PRINCIPAL SL BAWA DAVCOLLEGE BATALA PUNJAB

Abstract

Till today corruption in India remains a key problem in her development . Though India has improved its ranking in the ease of doing business but corruption at levels is hammering the positivity in its growth. This analytical paper critically studies the impediments blocking Indian economy. It also identifies the parameters needed for improving its position in the world order.

केंद्र सरकार के लिए विश्व बैंक की एक रिपोर्ट सुकून की खबर लाई है इसके मुताभिक कारोबार करने की सहूलियत के मामले में भारत की अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग में सुधार हुआ है विश्व बैंक की ओर से जारी पिछले साल की 130वां रैंकिंग के मुकाबले इस साल भारत की रैंकिंग 100 पर पहुंच गई है विश्व बैंक ने इस साल के आकलन में भारत को कारोबार करने के माहौल में सुधार करने वाले शीर्ष 10 देशों में रखा है यह आकलन 10 बिन्दुओ के आधार पर किया गया है और रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने इन 10 बिन्दुओ में से 8 में सुधार किए हैं

रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि इस साल भारत ही एकमात्र ऐसा देश है, जिसने इतना महत्वपूर्ण बदलाव दिखाया है भारत ने साल 2003 से अभी तक 37 सुधार किए हैं. इनमें से क़रीब आधे सुधार पिछले चार सालों में किए गए हैं इस रिपोर्ट में 190 देशों में 2 जून, 2016 से लेकर 1 जून, 2017 की अवधि में किए गए सुधार शामिल किए गए हैं

यह अध्ययन सिर्फ़ देश के बड़े शहरों में किया किया गया है. इन शहरों में कारोबार शुरू करना, कंस्ट्रक्शन परमिट लेना, ऋण उपलब्धता, अल्संख्यक निवेशकों की सुरक्षा, टैक्स का भुगतान, सीमा पार कारोबार, अनुबंध लागू करना और दिवालियेपन के समाधान जैसे संकेतकों में सुधार हुआ है.

रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत ने अल्पसंख्यक निवेशकों की सुरक्षा, ऋण और बिजली की उपलब्धता के क्षेत्र में अच्छा प्रदशर्न किया है. भारत अल्पसंख्यक निवेश की सुरक्षा में वैश्विक रैंकिंग में चौथे स्थान पर पहुंच

गया है साथ ही भारत में बिजली कनेक्शन मिलने का समय चार साल पहले के 138 दिनों से घटकर 45 दिन रह गया है

विश्व बैंक की रिपोर्ट की कई बातें सही हैं. करोबार को बढ़ावा देने के लिए पैन और टैक्स नंबर को आपस में इंटीग्रेट करना अच्छा कदम है इसी तरह कंस्ट्रक्शन परमिट को आसान किया गया है सरकार ने निश्चित रूप से सुधार किए हैं. विश्व बैंक का अध्ययन सही है, लेकिन रैंकिंग में सुधार के साथ-साथ तीन-चार जगह रैंकिंग घटी भी है बिजली में रैंक 26 से 29 हो गया. इसी तरह सीमा पार व्यापार में रैंकिंग 143 से 146 हो गई है और कारोबार शुरू करने में 155 से 156 हो गई है इनमें जो सबसे प्रमुख है, वह है 'एंफ़ोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट' जो अपने देश में बिज़नेस के लिए सबसे बड़ी समस्या है आज अगर कोई कारोबार के लिए अनुबंध करता है और दूसरा व्यक्ति उससे मुकर जाता है या धोखा देता है तो हम उसे नियंत्रित नहीं कर पाते इस मामले में मामूली सुधार हुआ है इस बिंदु पर 190 देशों में हम 172वें नंबर पर थे और अब सुधरकर 164 पर आए हैं

रिपोर्ट में एक और समस्या यह है कि इन्होंने सिर्फ देश के बड़े शहरों में अध्यन किया है इन शहरों में बड़े कारोबार हैं. पर सवाल यह है कि क्या देश के छोटे कारोबारियों के लिए कारोबार करना आसान हो गया है? आम आदमी और छोटे बिज़नेस करने वालों के लिए वांछित सुधार नहीं हुआ है इसके इलावा वहीं, बड़े कारोबार में भी मौलिक मुद्दों पर सुधार नहीं हुआ है अब अगर विदेशी निवेशकों की बात करें तो वह पहले भी कारोबार के लिए रास्ता निकाल लेते थे. जब भारत की रैंकिंग ख़राब थी, तब भी निवेश आता रहा है कटु सत्य यह भी है की इसके अलावा पिछले साल क़रीब सात महीनों में जो एफडीआई (विदेशी निवेश) आया, वो 26 बिलियन डॉलर था. लेकिन उसके बाद 22 बिलियन डॉलर ही आया. यानी एफ़डीआई भी आना कम हो रहा है सवाल यह है कि अगर रैंकिंग सुधर रही है तो एफ़डीआई कम क्यों आ रही है? इसके पीछे ठोस कारण ये है कि देश के बाज़ार में मांग नहीं है और नीतिगत स्तर पर मांग पैदा करने का कोई उपाय नहीं हुआ है रिज़र्व बैंक के डेटा के अनुसार छोटे बिज़नेस को दिए जाने वाले ऋण में गिरावट आ रही है. अगर उनके लिए सुधार हो रहा होता तो उनका ऋण बढ़ता विश्व बैंक की रिपोर्ट में कहा गया है कि अल्पसंख्यक निवेशकों की सुरक्षा में सुधार हुआ है लेकिन इसका छोटे कारोबार से क्या लेना-देना है? उनके लिए तो अनुबंध का लागू होना सबसे ज़रूरी है इस

मामले में पहले हमें अनुबंध लागू करवाने में 1420 दिन लगते थे जो अब बढ़कर 1445 हो गए हैं. यानी हम पिछड़ते जा रहे हैं

इस रिपोर्ट में भ्रष्टाचार का ज़िक्र नहीं है. एक नया कारोबार शुरू करने के लिए कितनी घूस देनी पड़ती है इसमें ज़मीनी सुधार नहीं हुआ है सरकार को निवेश में बढ़ोतरी के मामले चिंतित होना होगा क्योंकि देश में मांग ही नहीं है कोई भी निवेश बिना मांग के नहीं आता है. सरकार ने जीएसटी और नोटबंदी से देश की आय को बाहर भेजना चालू कर दिया क्योंकि इसके बाद सोने की ख़रीद दोगुनी हो गई है अब धन बाहर जा रहा है तो यहां मांग कैसे बढ़ेगी? इसके बावजूद आर्थिक सुधारों के मामले में सरकार की स्थिति संतोष जनक है

References

- "The World Factbook". www.cia.gov. Retrieved 7 June 2017.
- "5th Annual Employment-Unemployment Survey Report 2015-16" (PDF). Labour Bureau. Archived from the original (PDF) on 13 November 2016. Retrieved 12 November 2016.
- GDP of India and major Sectors of Economy Archived 30 April 2014 at the Wayback Machine. Government of India (2013)
- Foreign Trade Performance of India Annual Report Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics, Ministry of Commerce and Industry, Government of India (2012)
- "Ranking of economies - Doing Business - World Bank Group". www.DoingBusiness.org. Retrieved 2 November 2017.
- "India - WTO Statistics Database". World Trade Organization. Retrieved 1 March 2017.
- "Country Fact Sheets 2016". unctad.org. Retrieved 5 July 2017.
- Nayak, Gayatri (15 June 2017). "CAD soars to $3.4 b or 0.6% as imports jump in Q4". The Economic Times. Retrieved 19 November 2017.
- Mishra, Asit Ranjan (15 June 2017). "India current account deficit rises year-on-year as imports jump in Q4". Mint. Retrieved 19 November 2017.
- "India's External Debt as at the end of March 2017" (PDF). RBI. Retrieved 5 July 2016.

- "India's External Debt". Ministry of Finance, Government of India. September 2016. Retrieved 3 November 2016.
- "International Investment Position". Reserve Bank of India. 29 December 2017. Retrieved 6 February 2018.
- "World Economic Outlook Database, April 2017 - Report for Selected Countries and Subjects - General government gross debt". International Monetary Fund. Retrieved 4 July 2017.
- "Report for Selected Countries and Subjects - General government revenue/General government total expenditure". IMF. Retrieved 18 February 2017.
- "Net official development assistance received (current US$)". World Bank. Retrieved 25 May 2017.
- "Sovereigns rating list". Standard & Poor's. Retrieved 26 May 2011.
- "Moody's upgrades India's government bond rating to Baa2 from Baa3; changes outlook to stable from positive". Moody's. 30 November 2017. Retrieved 16 November 2017.
- "Fitch - Complete Sovereign Rating History". Retrieved 2013-02-25.
- "Weekly Statistical Supplement - Foreign Exchange Reserves".
- Sumit, Ganguly (2011). India Since 1980. Cambridge University Press. ISBN 9781139498661.